



षोडश
बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 09 अग्रहायण, 1939 (श10)
30 नवम्बर, 2017 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	01
(2) कृषि विभाग	01
(3) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	02
कुल योग —			<u>04</u>

राशि खर्च करना

7. श्री भाई वीरेन्द्र-स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित शीर्षक "राशि खर्च नहीं होने पर कृषि विभाग सख्त, अफसरों से माँगा गया व्यौरा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि द्वितीय कृषि रोड मैप के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये विभाग को आवंटित राशि का पूरे राज्य में छः माह बीत जाने के बावजूद मात्र 15 प्रतिशत ही राशि खर्च हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषियों पर कार्रवाई

8. डॉ० रामानुज प्रसाद-स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जुलाई, 2017 को प्रकाशित शीर्षक "बाइक से भी होंगे गये सैकड़ों बोरे धान" के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य भर में वर्ष 2011-14 तक दर्ज कुल 1,202 चावल आपूर्ति घोटाला के मामलों की पड़ताल के लिये सरकार ने एस0आई0टी0 का गठन किया गया है जिसमें जॉचोपरान्त एस0आई0टी0 ने पाया है कि हजारों टन धान बड़ी गाड़ियों के बदले मोटर साइकिल से होया गया है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अभीतक दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

9. श्री अत्री मुनि उर्फ शाकिा सिंह यादव-क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 में ख) 4,000 करोड़ का धान खरीद घोटाला मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लगभग 15,000 (पन्द्रह हजार) F.I.R दर्ज हुआ है परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार दोषी पदाधिकारियों एवं दोषी व्यक्तियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

10. माँ० नेमातुल्लाह-क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिलों में सूलभ शौचालय के निर्माण की आड़ में विभागीय अभियंताओं द्वारा अरबों रुपया का घोटाला सरकारी खजाने से की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला में एन0जी0ओ0 एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा चौदह करोड़ रुपया का घोटाला प्रकाश में आने पर पटना गाँधी मैदान धाने में दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को एक एफ0आई0आर0 भी दर्ज किया गया है, यदि हाँ, तो राज्य के बाकी जिलों में इस अनियमितता की जाँच करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

पटना :
दिनांक 30 नवम्बर, 2017 (ई०) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 68-डी०टी०पी०-550